

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 16, शुक्रवार, शाके 1942-फरवरी 5, 2021 <i>Magha 16, Friday, Saka 1942- February 5, 2021</i>	

भाग-3(ख)

सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपनी सहज शक्तियों के प्रयोग में, बनाये जाने को प्रस्तावित प्रारूप नियम, अनियम, उप-नियम और आज्ञायें ।

(मत्स्य विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 13, 2021

पत्रावली संख्या 5(8)पपा/97 :-यतः राजस्थान मत्स्य नियम, 1958 को और संशोधित करने के लिए प्रारूप नियम, उनसे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों से, उस तारीख जिसको राजस्थान राजपत्र में यथा प्रकाशित उक्त प्रारूप नियमों की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं, से 21 दिवस के अवसान से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए राजस्थान मत्स्य अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 16) की धारा 5 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 3 (ख) में दिनांक 07.03.2019 को प्रकाशित किये गये थे।

और यतः उक्त प्रारूप नियमों की अधिसूचना की प्रतियां जनता को 29.03.2019 को उपलब्ध करा दी गयी थीं;

और यतः राज्य सरकार को कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अब, राजस्थान मत्स्य अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मत्स्य नियम, 1958 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मत्स्य (संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. नये नियम 5क का अंतःस्थापन.- राजस्थान मत्स्य नियम, 1958 के विद्यमान नियम 5 के पश्चात् और

विद्यमान नियम 6 से पूर्व निम्नलिखित नया नियम 5क अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“5क. नियम 5 के उप-नियम (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नगरपालिका द्वारा प्रशासित क्षेत्रों को छोड़कर, संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में यथा निर्दिष्ट राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित जलाशयों को, रजिस्ट्रीकृत जनजाति मछुआरा सहकारी सोसाइटी को नियम 5 के उप-नियम (5) के खण्ड (i) के उप-खण्ड (ख) के अधीन अवधारित आरक्षित कीमत पर आबंटित किया जा सकेगा। ‘ख’ प्रवर्ग के जलाशय का जिला परिषद् द्वारा तथा ‘ग’ और ‘घ’ प्रवर्ग के जलाशय का पंचायत समिति द्वारा आबंटन किया जायेगा।”

राज्यपाल के आदेश से,
कुंजी लाल मीणा,
प्रमुख शासन सचिव।

(FISHERIES DEPARTMENT)**NOTIFICATION****JAIPUR, January 13, 2021**

File No. 5(8)AH/97 .-Whereas the draft rules further to amend the Rajasthan Fisheries Rules, 1958 was published in the Rajasthan Gazette Extraordinary, Part 3 (B) dated 07.03.2019 as required by sub-section (1) of section 5 of the Rajasthan Fisheries Act, 1953 (Act No. XVI of 1953) for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of 21 days from the date on which the copies of the said notification as published in Rajasthan Gazette were made available to the people on 29.03.2019 .

And whereas no objections and suggestions have been received by the State Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Rajasthan Fisheries Act, 1953 (Act. No. XVI of 1953), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Fisheries rules, 1958 namely:-

1. **Short title and Commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Fisheries (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Insertion of new rule 5A.-** After the existing rule 5 and before the existing rule 6 of the Rajasthan Fisheries Rules 1958, the following new rule 5A shall be inserted, namely:-

" 5A. Notwithstanding anything contained in sub-rule (5) of rule 5, waters, situated in Scheduled Areas of Rajasthan as referred to in clause (1) of Article 244 of the Constitution except those areas which are administered by a municipality, may be allotted to the Registered Tribal Fisherman Cooperative Society on reserve price determined under sub-clause (b) of clause (i) of sub-rule (5) of rule 5. Allotment of the B category water shall be made by the Zila Parishad and C and D category water shall be made by the Panchayat Samiti."

**By Order of the Governor,
KUNJI LAL MEENA,
PRINCIPAL SECRETARY TO THE GOVERNMENT.**

Government Central Press, Jaipur.